THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHIR CHATURANAN MISHRA): (a) On the basis of the information received from the State Governments, a Statement indicating loss of human and animal lives and damage to houses and crops in different States due to heavy rains cyclones and floods during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 is given at Annexure-[*See Appendix 178, annexure no. 97]*

(b) For undertaking relief and rehabilitation measures in the wake of natural calamities, a Calamity Relief Fund (CRF) has been constituted in each State, which is shared by the Central and State Governments in the ratio of 3:1. From 1995-96 a National Fund for Calamity Relief (NFCR) has also been constituted for providing additional assistance to the State in the wake of calamit of rare severity. A Statement indicating funds released from the Central share of CRF during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 and the additional funds released from the NFCR for 1995-96 is given at Annexure-[*See Appendix 178, annexure no. 97].*

(c) The State Governments are undertaking various measures such as embankments, drainage channels, town protection, raising of villages and anti-erosion works as part of the Plan Programmes, for permanent solution to the problem of flood.

शैक्षिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया गया अनुदान

4038. **श्री अजीत जोगी:**
श्रीमती वीणा वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक अभियान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही शैक्षिक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं, जिनमें ये गतिविधियां चलाई जा रही हैं और इन गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे संस्थानों को राज्य वार कितना-कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को समुचित ढंग से चलाने की दृष्टि से इन गतिविधियों की समीक्षा करने के लिये कोई समिति गठित की गई है अथवा कोई और व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राज सैकिया): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार आपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक शिक्षा योजना, अनौपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन) आदि जैसी कई केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं के विवरण तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई सहायता की राशि इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई है। ये वार्षिक रिपोर्टें माननीय संसद सदस्यों को परिचालित कर दी गई हैं। प्रत्येक योजना की निगरानी करने के लिए तंत्र बनाए गए हैं।

Omission of major drugs from Drug price Control Order

4039. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that major drugs have been omitted from the laster 'Drug Price Control Order';

(b) whether curtailing the list of the controlled drugs has led to a sharp increase in the prices of a number of medicines in the country; and

(c) if so, whether Government propose to reconsider their decision?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA): (a) Selection of drugs for price control has been done on the basis of the criteria, as laid down in the 'Modificaitons in the Drug Policy, 1986'.